

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी कमला अलारिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 38/2014

दायरा दिनांक 25.03.2014

1. नन्दलाल पुत्र सरदाराराम } अकवाम मेघवाल साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील
 2. केसर देवी बेवा सरदाराराम } सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। -प्रार्थी
- बनाम
- 1 चम्पालाल पुत्र श्री हरचन्द जाति मेघवाल साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
 - 2 तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। - अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-


दिनांक: 23.02.2022

शिकायत अर्न्तगत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

- उपस्थित :-1. श्री कमलदत्त शर्मा व रामस्वरूप तावणीया :-अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :-अप्रार्थी न. 1 की और से
- 3.पैरोकार राजतहसीलदार सूरतगढ़ :-अप्रार्थी न. 2 की और से


पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया, कि अप्रार्थी न. 1 के पिता हरचन्द पुत्र आशाराम जाति मेघवाल साकिन भैरुपुरा के नाम से रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 288 में 17.00 बीघा व खसरा न. 176 में 23.15 बीघा इस प्रकार कुल 40.15 बीघा रकबा अस्थाई आवंटन था। जो सवतं 2043 तक नवीनीकरणशुदा है। उसके बाद अप्रार्थी के पिता को 34.00 बीघा रकबा ही अस्थाई आवंटन नवीनकरण होता आ रहा है। 6.15 बीघा रकबा काट दिया था तथा अप्रार्थी के पिता के पुख्ता आवंटन के समय 34.00 बीघा रकबा ही स्थाई आवंटन हुआ था। 6.15 बीघा रकबा का सरप्लस का कोई साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थी न. 1 ने अपने पिता को शेष रकबा ना होते हुए भी तथा कब्जा काश्त न होते हुए भी बालिग पुत्र में यह रकबा आवंटन करवा लिया है। जब रकबा राज ही नहीं था व बालिगपुत्र में भी नहीं था व कब्जा काश्त में नहीं था तो आवंटन नहीं हो सकता है। यह रकबा पचायत समिति सूरतगढ़ के नाम दर्ज है। तथा अप्रार्थी ने रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 से पैमुद चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 के किला न. 14 ता 19, 25 का 1.682 हैक् रकबा अपने पिता का अधिशेष बताकर श्रीमान आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ से मिसल न. 2345/2007 बअनवान चम्पालाल बनाम सरकार से जो 1.682 हैक् रकबा दिनांक 15.07.2007 को आवंटन करवाया है, यह आवंटन खारिज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इन्कार करते हुए जबाब पेश किया कि अप्रार्थी के पिता के नाम से रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 176 में कोई रकबा नहीं है। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी के पिता हरचन्द पुत्र आशाराम जाति मेघवाल के नाम से रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में 23.13 बीघा व खसरा न. 288 में 17.00 बीघा कुल 40.13 बीघा रकबा टी सी आवंटन था। पुख्ता आवंटन के समय श्रीमान आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने दिनांक 08.01.1990 को खसरा न. 288 का तमाम 17.00 बीघा व खसरा न. 167 का 23.13 बीघा रकबा में से 17.00 बीघा इस प्रकार कुल 34.00 बीघा बारानी भुमि अप्रार्थी के पिता को पुख्ता आवंटन कर दी। परन्तु 6.13 बीघा रकबा के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये। इस पर अप्रार्थी


जिला कलक्टर
गढ़ (श्री गंगानगर)

के पिता ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील न. 170/92 पेश की जो दिनांक 20.01.1993 को स्वीकार हो गई व अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी के पिता के नाम से रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 का 6.13 बीघा रकबा अधिशेष घोषित कर दिया। इस रकबा पर अप्रार्थी का लगातार कब्जा चलता रहा व श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की कार्यवाही भी करते रहे। नाजायज काश्त की पत्रावलीयों की फोटो प्रतियां सलग्न जवाब पेश की। यरवत पुख्ता आंवटन श्रीमान आवटन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को रकबा के लिए दिनांक 03.09.2007 को सक्षम घोषित कर यह रकबा सलाहाकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु रखे जाने का आदेश दिया व दिनांक 15.09.2007 को पत्रावली न. 2349/2007 में उक्त रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में 6.13 बीघा रकबा पूर्णतया विधी सम्मत तरीके से अप्रार्थी की पात्रता की पुरी जाँच कर अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध उक्त दोनो शिकायत कर्ता ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील न. 79/2012 बअनवान केसरदेवी आदि बनाम चम्पालाल प्रस्तुत की जो दोनो पक्षो को व सरकार को सुनकर मुझ अप्रार्थी का आवंटन विधी सम्मत पाये जाने पर प्रार्थीगण की यह अपील दिनांक 15.01.2014 को खारिज कर दी। तथा इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भी निगरानी पेश कर रखी व मुझ अनूसूचित जाति के गरीब काश्तकार को परेशान करने के लिये प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय ने यह शिकायत पेश कर दी है। रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में कुल 101.13 बीघा रकबा था इसमें से 23.13 बीघा रकबा मेरे पिता हरचन्द का टी सी आवंटित रकबा था तथा 15.00 बीघा रकबा प्रार्थीगण के पति/पिता सरदारा का था। शेष रकबा अन्य काश्तकारो व पचायत समिति का था। चक बन्दी के दौरान इस खसरा के काश्तकारो का अलग रकबा पैमुद हुआ है चकबन्दी का कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी के रकबा से चक बन्दी के दौरान चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 के किला न. 14 ता 19, 25 का 1.683 हैव रकबा पैमुद हुआ है। अप्रार्थी ने पुख्ता आवंटन के पश्चात इस रकबा की तमाम किश्ते जमा करवा दी है। तथा आवंटन की तमाम शर्ता की पालना करने पर अप्रार्थी के नाम से श्रीमान आवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने खातेदारी सनद संख्या 3556 दिनांक 16.01.2016 को जारी कर दी है व राजस्व रिकार्ड मे यह रकबा मुझ अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी ने श्रीमान आवटन अधिकारी के समक्ष किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है तथा पुख्ता आवंटन के वक्त कोई झुठे व मिथ्या तथ्य पेश नहीं किये है तथा अप्रार्थी का पेशा काश्तकारी व अप्रार्थी राजस्थान का मुल निवासी है। अप्रार्थी उक्त रकबा बालिग पुत्र मे आवंटन का हकदार था। प्रार्थी ने महज परेशान करने के लिए यह झुठा शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी तथ्यो को मिथ्या या गलत सुचना दी जावे तो लागु होता है परन्तु अप्रार्थी ने न तो कोई गलत सुचना दी है न कोई तथ्य छुपाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ से भी रिपोर्ट मगवाई जो शामिल पत्रावली है। तत्पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के समय अपने शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा के बाबत पत्रावली में कोई सरप्लस के साक्ष्य नहीं है तथा अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी का आवंटन खारिज किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने न तो कोई तथ्य छुपाये है व न ही झुठे तथ्य पेश किये है तथा रकबा खातेदारी होने के पश्चात इस न्यायालय को इस धारा मे कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है इस पर काश्तकारी अधिनियम लागु हो गया है तथा उपनिवेशन अधिनियम मे धारा 21 मे आंवटन अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के आंवटन के विरुद्ध अपील पेश की थी जो खारिज हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व झुठी शिकायत करने पर प्रार्थी को तथा कानूनी नजीर आर आर डी 2009 पेज न. 177, 99, आर आर टी 2003 पेज न. 984, आर आर टी 2011 पेज न. 270, आर आर डी 2007 पेज न. 480, डी एन जे 1999 पेज न. 509 पेश किया।


 त जिला कलक्टर
 मड (श्री गंगानगर)

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। यह बात सही है कि अप्रार्थी के पिता हरचन्द को रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 के 23.13 बीघा व खसरा न. 288 में 17.00 बीघा कुल 40.13 बीघा रकबा सँवत 2028 से यानी आज से 50 वर्षों पहले से टी.सी. आवंटन है तथा आवंटन अधिकारी सूरतगढ ने पुख्ता आवंटन के समय दिनांक 08.01.1990 को दोनो खसरो मे 17.00-17.00 बीघा कुल 34.00 बीघा रकबा तो पुख्ता आवंटन कर दिया परन्तु खसरा न 167 के शेष रहे 6.13 बीघा रकबा के लिए कोई आदेश नहीं हुआ जो अपील न. 170/1992 में श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने दिनांक 20.01.1993 को निर्णय करते हुए रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 के 6.13 बीघा रकबा अप्रार्थी के पिता हरचन्द के नाम से सरप्लस कर दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाजायज काश्त की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियो से साबित है कि अप्रार्थी का इस सरप्लस शुदा रकबा पर लगातार कब्जा काश्त है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 22 की पत्रावलीयो के अनुसार तहसीलदार सूरतगढ ने अनेको बार अप्रार्थी न. 1 के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही अप्रार्थी के पुख्ता आवंटन से पूर्व की है इसलिये इस रकबा पर अप्रार्थी का कब्जा ना हो साबित नहीं है तथा अतिक्रमण के आधार पर ऑवटन खारिज भी नहीं किया जा सकता । आवंटन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को पत्रावली न. 2349/2007 में दिनांक 03.09.2007 को इस 6.13 बीघा के लिए सक्षम घोषित किया है व दिनांक 15.09.2007 को सलाहाकार समिति से यह रकबा अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन हुआ है तथा इस आवंटन के खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपील न. 79/2012 श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की थी जो दिनांक 15.01.2014 को खारिज हो चुकी है। चक बन्दी के दौरान यह रकबा चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 में 1.682 हैक् रकबा पैमुद हुआ है तथा इस रकबा के खातेदारी सनद दिनांक 06.01.2016 को अप्रार्थी के नाम से जारी हो चुकी है। प्रार्थीगण ने पहले अप्रार्थी के ऑवटन के विरुध अपील पेश कर दी है व अब इस न्यायालय मे यह शिकायत पेश कर दी है परन्तु अप्रार्थी को उक्त रकबा ऑवटन विधी सम्मत मानकर ही श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय श्रीगंगानगर ने शिकायत कर्ता की अपील खारिज कर दी तथा ऑवटन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को पुख्ता ऑवटन करने मे कोई त्रुटि नहीं की है तथा शिकायतकर्ता तथा राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी ने अपने ऑवटन पत्रावली मे कोई मिथ्या तथ्य/गलत सुचना पेश करके या सही तथ्य छिपाकर के यह आवंटन करवाया हो तथा इस रकबा के बाबत अप्रार्थी ने आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष कोई गलत सुचना दी हो ऐसा साक्ष्य भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। प्रकरण में मिथ्या सुचना का या न्यायालय से कपट का कोई प्रकरण नहीं बनता है, इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का शिकायत प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन व मनगढत होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ (गंगानगर)